Need to review inclusion of Muzaffarnagar and Shamli districts in National Capital Region-Laid

सुश्री इकरा चौधरी **(**कैराना**) :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्रीय योजना 2021 को एनसीआर क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था । हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है । किसान और छोटे व्यवसाय मालिक इस समावेशन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं । वाहन स्क्रैपेज नीति जैसी नीतियां, जो दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में असमान रूप से प्रभाव डालती हैं । विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर जिले में किसान और ईंट भट्ठा संचालक पुराने वाहनों और उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें अब अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है । ऐसे उपकरणों को बदलना एक बड़ा आर्थिक बोझ है, जहां आय कम होती है और विकल्प सीमित होते हैं ।इसके अतिरिक्त, इन नव-शामिल जिलों के विकास के लिए आवंटित धनराशि में पारदर्शिता का अभाव है, और यह स्पष्ट नहीं है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है । सरकार को शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के समावेशन पर पुनर्विचार करना चाहिए । विकास नीतियों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करें ।